भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2591
दिनांक 22 **दिसंबर**, 2022

सरकारी स्वामित्व वाली तेल विपणन कंम नियां

†2591. **श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश की सरकारी स्वामित्व वाली उन तेल विपणन कंम नियों (ओएमसीज़) का ब्यौरा क्या है, जिन्हें वर्ष 2014 से वर्चुअल रूप से खुदरा कीमतों को फ्रीज किए जाने के कारण पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर हानि हुई है; और

(ख) उक्त प्रकार के वर्चुअल फ्रीज के कारण क्या है और सरकार द्वारा इस तरह के नुकसान को कम करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख) वर्ष 2014 से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंम नियों (ओएमसीज) का करोपरांत स्टेण्डअलोन लाभ/(हानि) निम्नवत हैः

(करोड़ रुपए)

ओएमसीज	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	(**अप्रैल** 2022-**सितंबर** 2023) (**पी**)
आईओसीएल	5,273	11,242	19,106	21,346	16,894	1,313	21,836	24,184	(2,265)
बीपीसीएल	5,085	7,056	8,039	7,919	7,132	2,683	19,042	8,789	(6,567)
एचपीसीएल	2,733	3,725	6,209	6,357	6,029	2,637	10,664	6,383	(12,369)

स्रोतः पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) पी- अनंतिम

पेट्रोल और डीजल के मूल्य क्रमशः दिनांक 26.06.2010 और 19.10.2014 से बाजार निर्धारित हैं। तब से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंम नियां (ओएमसीज) पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण के संबंध में उचित निर्णय लेती है।

सरकार उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी के प्रभावी मूल्य को आवश्यकतानुसार घटाती-बढाती रहती है। अप्रैल 2020 से अप्रैल 2022 तक की अवधि के दौरान एलपीजी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी मूल्यों में हो रहे उतार-चढ़ाव से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए लागत में हुई वृद्धि का बोझ घरेलू एलपीजी के उपभोक्ताओं पर पूरी तरह से नहीं डाला गया था जिससे इन ओएमसीज को काफी हानि हुई है। हानि की भरपाई करने के लिए सरकार ने हाल ही में ओएमसीज को 22,000 करोड़ रुपए का एकबारगी मुआवजा अनुमोदित किया है।

*****